

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1974/फाल्गुन 9, 1895

No. 50] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 1974/PHALGUNA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## बजट 1974-75 वित्त मंत्री का भाषण 28 फरवरी, 1974

महोदय,

मैं आपकी अनुमति से 1973-74 के संशोधित अनुमान और 1973-74 के लिए बजट अनुमान पेश करता हूँ।

2. यह संघ सरकार का नियमित, चौथा बजट है, जिसे सदन के सामने पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक केन्द्रीय बजट का मुख्य-लक्ष्य यह होता है कि द्रुत विकास, स्थायित्व, अधिक से अधिक सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता लाने की आवश्यकताओं के बीच उचित समन्वय लाया जाय। लम्बी अवधि में ये उद्देश्य एक दूसरे के पोषक होते हैं। छोटी सी अवधि में इन उद्देश्यों में समन्वय लाना, चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल भी हों, कोई सरल काम नहीं होता। पिछले तीन सालों में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहीं, असल में वह अनेक प्रकार से, सामान्य भी नहीं रहीं। इन तीन सालों में हर साल हमें नई

नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो एक से एक भारी थीं। हमने उन चुनौतियों का अपनी पूरी ताकत से सामना करने की कोशिश की। हालांकि मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तत्त्वों के कारण जिन पर हमारा वश नहीं था ऐसी असामान्य भारी मजबूरियाँ आयीं कि हम जितनी प्रगति की आशा करते थे उतनी नहीं कर सके।

3. मैं यह बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि अगले वित्तीय वर्ष में अर्थ व्यवस्था को और भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तब इस बात की आजमाइश होगी कि हमारी अर्थ व्यवस्था कितनी पुरजोर है और उसमें हालात के अनुसार अने को ढालने की कितनी सामर्थ्य है। कच्चे तेल व कुछ दूसरी चीजों की कीमतों के बहुत तेजी से बढ़ जाने से व्यापार की स्थिति हमारे एकदम उल्टी हो गयी है और इससे हमारा काम असामान्य रूप से कठिन हो गया है। लेकिन हाल की घटनाओं पर विचार करते समय इतिहास के लम्बे दौर का ध्यान रखना चाहिए। दुनियाँ में कहीं पर भी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव हुए बिना, आसानी से नहीं हुए। इसलिए मुझे इस सबसे घबड़ा उठने या अपने बुनियादी लक्ष्यों व उद्देश्यों के बारे में झंका कर बैठने की कोई वजह नहीं दिखायी पड़ती। हमारे सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने के थे पहले थे। हम अपने लक्ष्य हासिल करने में उतने ही कृत संकल्प हैं जितने पहले थे। हम गरीबी, अज्ञानता व बीमारियों के खिलाफ हथियार इसलिए नहीं ढाल सकते कि यह लड़ाई आशा से अधिक भारी पड़ रही है, हालांकि हो सकता है कि परिस्थिति के अनुरूप हमें अपने साधन बदलने पड़ें।

#### अर्थ-व्यवस्था

4. जैसा कि सदन को मालूम है, सरकार कीमतों की तेजी के भारी बोझ के बारे में बहुत चिंतित रही है। यह बोझ पिछले दो वर्षों से हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बोझ को दूर करने के लिए जो उपाय किये गये वह सम्मानित सदस्यों को मालूम हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इन उपायों के बावजूद कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सदन को भली भाँति ज्ञात है कि लगातार दो वर्षों, 1971-72 व 1972-73 में खेती के उत्पादन में सन्तोषजनक परिणाम न मिलने के कारण कीमतों पर असर पड़ना अवश्यंभावी था। 1972-73 में खेती की पैदावार के तेजी से 9.5 प्रतिशत गिर जाने से मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन का उलट पुनट हो जाना स्वभाविक था। विदेशों से हमने भारी मात्रा में जो अनाज मंगाया उससे भी देश में कीमतों का बढ़ना नहीं रक सका। जिसका कारण यह रहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें और ज्यादा बढ़ गयीं थीं। 1973 में श्रौत से अधिक खरोफ की पैदावार होने पर भी कीमतें नीचे न उतर सकी क्योंकि अर्थ व्यवस्था में कीमतों में वृद्धि करने वाली कुछ दूसरी शक्तियाँ सक्रिय रहें।

5. ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आय में 1973-74 में निश्चय ही उल्लेखनीय वृद्धि होगी, इससे पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आय की असन्तोषजनक स्थिति के सुधरने में सहायता मिलेगी। फिर भी यह सभी के लिए विशेष चिन्ता की बात है कि चौथी आयोजना में हमारे सारे विकास की दर आयोजना के लक्ष्य से काफी कम थी। यह भी हमारे लिए विशेष चिन्ता की बात है कि औद्योगिक उत्पादन में जो प्रगति 1972 में दिखायी दी वह 1973 में बनी न रह सकी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1973 में औद्योगिक उत्पादन की दर में मुश्किल से कोई प्रगति हुई होगी। हमारी आर्थिक नीति का प्रधान

उद्देश्य यह होगा कि 1974 में औद्योगिक कार्यकलाप में फिर से तेजी लायी जाय। विकास की असीम दर की प्राप्ति एक चुनौती है जिसका सामना हमें पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में करना है।

6. जैसा कि सदन को पता है कि देश में मज्दाई को पूरा करने के लिए विदेशों से 1973-74 में सरकार ने खाद्यान्न व वनस्पति तेल पर्याप्त मात्रा में आयात किया। राष्ट्र की सुविधा के लिए यह आयात जरूरी था लेकिन इससे हमारे आयात का खर्च बढ़ गया। सांभाध्य से हमारे निर्यात में सन्तोषजनक रीति से वृद्धि हुई है और हमारे भुगतान सन्तुलन में जो भी कमी आ गयी थी वह इसी वृद्धि के कारण इतनी हल्की रह गयी कि उस पर काबू पाया जा सकता है। फिर भी हमारे भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि यह कच्चे तेल व दूसरी चीजों जैसे उर्वरक व अलोह धातुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण स्वाभाविक रूप से और ज्यादा हो जाएगा। आगे चल कर हमारे व्यापार में इस भारी परिवर्तन के साथ संतुलन बनाये रखने के लिए व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण हमारी अर्थ-कदम उठाया जा सकता है जिससे कि हमारे विकास पर कोई असर न पड़े, वह यह है कि जहां भी हो सके तेल की जगह देश में ही मिलने वाली उर्जा का इस्तेमाल किया जाय तथा तेल निकालने के कार्य क्रमों में तेजी लायी जाय। इस संदर्भ में कोयले के उत्पादन को जल्दी से जल्दी व ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है फिर भी, हमारे आयात के खर्च का बढ़ना अनिवार्य है इससे यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने निर्यात में वृद्धि करें। तेल के संकट से हमारी कठिनाइयां जरूर बढ़ गई हैं लेकिन इससे जूट के कपड़े, सूती कपड़े व चमड़े की चीजों जैसे उत्पादनों का निर्यात करने के लिए नये क्षेत्र भी मिल गये हैं। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का फायदा उठायें और इस बात की पूरी कोशिश करें कि हम निर्यात से अधिक से अधिक आमदनी कर सकें। निर्यात की सारी संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा से हमें निर्यात की क्षमता का 'पूरा-पूरा' उपयोग करने के लिए एक सुगठित कार्यक्रम शुरू करने में सहायता मिलेगी।

7. पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि देश के सामने सबसे ज्यादा जरूरी काम है अर्थ व्यवस्था की स्फीति पर नियंत्रण, बचत करने व पूंजी लगाने के काम में उत्तरोत्तर वृद्धि, विदेशी भुगतान की क्षमता में वृद्धि करना व ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोजगार दिलाना। पिछले एक साल में कीमतों में भारी वृद्धि, व तेल दूसरी अंतरराष्ट्रीय चीजों की कीमतों के चढ़ जाने से भुगतान संतुलन पर भारी दबाव पड़ने व 1973 में औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आ जाने से उपर जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है उनको पूरा करना और अधिक आवश्यक हो गया है। हालांकि पिछले साल हमारी अर्थ व्यवस्था के परिणाम तुलना करने पर अच्छे नहीं रहे इससे सन्देह, अनिश्चय और गलती ठुंठने की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करें और जनता के इस विश्वास को बनायें रखें कि सामाजिक परिवर्तन लाने में हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था एक कारगर साधन है।

#### संशोधन अनुमान 1973-74

8. सदन को याद होगा कि 1973-74 के बजट अनुमान में 87 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था। इसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण होने वाला खर्च शामिल नहीं था क्योंकि आयोग की रिपोर्ट बजट प्रस्तावों को बनाते समय उपलब्ध नहीं थी। अनुमान किया गया था कि इन सिफारिशों को मंजूर करने से बजट का घाटा 87 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जायेगा। फिर भी, बाद की घटनाओं

से जो मुख्यतः 1972-73 में खेती के उत्पादन के काफी गिर जाने के कारण हुई, बजट की स्थिति जसी पहले सोची गई थी उससे काफी ज्यादा बिगड़ गई।

9. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 1972-73 में असाधारण व व्यापक सूखा पड़ने से जो सहा-याता कार्य शुरू किये गये थे उन्हें बड़े पैमाने पर 1973-74 में भी जारी रखा गया। जब यह कार्य अपनी चर्म सीमा पर था सारे देश में, 1,43,740 राहत केन्द्र खोले गये और 93 लाख लोगों को रोजगार मिला। आशा की गयी थी कि 1973-74 में मानसून शुरू होने पर खेती के काम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिलने लगेगी और जिन लोगों को सहायता कार्य पर लगाया गया उनकी संख्या काफी हद तक घट जायगी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार को इस मद में राज्य सरकारों को भारी मात्रा में सहायता देना जारी रखना पड़ा। सम्माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष के बजट में इस काम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी थी। यह व्यवस्था पूरी तरह से अपर्याप्त सिद्ध हुई और इसमें 220 करोड़ रुपये और डाल कर इसे बढ़ाना पड़ा।

10. इस संबंध में मैं सम्माननीय सदस्यों का ध्यान देवी विपदाओं से राहत पर खर्च के बारे में वित्त आयोग के सुझावों की ओर दिलाना चाहूंगा। आयोग ने इस बात का अनुरोध किया है कि राहत के लिए तदर्थ आधार पर खर्च करने के बजाय जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा करता है या जहाँ बाढ़ आया करती है ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं आयोजना में राज्य व केन्द्र के दोनों क्षेत्रों में पहले से ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सुझावों के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि इन कार्यक्रमों को जहाँ तक हो सके विकास योजनाओं के साथ मिला दिया जाय।

11. राज्य सरकारों को देवी विपदाओं में राहत पर खर्च करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन देने के अलावा इन सरकारों को अपने-अपने साधनों की कमी को पूरा करने व विशिष्ट आयोजनाओं के लिए बी जाने वाली विशेष सहायता के लिए रखी धनराशि में भी वृद्धि करनी पड़ी है। बजट में इस काम के लिए 198 करोड़ रुपये रखे गये थे और इस राशि में लगभग 91 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी।

12. केन्द्र के कोप को कुछ दूसरे खर्चों का बोझ भी उठाना पड़ा। अनाज की बिक्री कीमतों में कुछ फेर बदल करने के बावजूद अनाज के लिए बी जाने वाली सरकारी सहायता पर होने वाला खर्च 130 करोड़ रुपये की रखी गयी व्यवस्था से 121 करोड़ रुपये ज्यादा होगा। इसका मुख्य कारण विदेशों से मंगाये गये अनाज का मंहगा होना है।

13. सरकार के खर्च पर बढ़ती किमतों का सीधा असर यह पड़ा कि उसे अपने कर्मचारियों को इस साथ अधिक मंहगाई भत्ता देना पड़ा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय हमने मंहगाई भत्ता देने के लिए एक उदार फारमूला मंजूर किया था जिससे कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों को रहन-सहन के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल सके। इस फारमूले के आधार पर हमने मंहगाई भत्ते की चार किस्ते मंजूर की हैं जिन पर सरकार को 100 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

14. तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 150 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया था। यह एक भारी दायित्व था, विशेष कर ऐसी हालत में जब की देश के सामने कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। इस दायित्व की वजह यह थी कि हमसे यह आशा की जाती रही कि हम आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर लेंगे। सच तो यह है कि वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बारे में जो सिफारिशें की थीं हमने उन में उल्लेखनीय संशोधन करना मान लिया, अकेले इन संशोधनों से एक साल में 61 करोड़ रुपये आवर्ती व 25 करोड़ रुपये अनावर्ती आधार पर खर्च होने लगेंगे।

कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अपने साधनों पर जितना ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल सकती थी, डाल चुकी है। मुझे पूरी पूरी आशा है कि हमारे कर्मचारी भी इस बात को समझेंगे और काम करने की अपनी दक्षता व उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने की हर कोशिश करेंगे।

15. जहां तक आय का सवाल है, इसमें कुछ कमियां रही हैं। उद्योग के अनेक बड़े क्षेत्रों में कच्चे माल की कमी व बिजली की सप्लाई में कमी के कारण उत्पादन में ठहराव आ जाने से उत्पादन शुल्कों से होने वाली आमदनी पर पूरा असर पड़ा है। इससे 107 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।

16. जैसा कि रेल मंत्री ने कल कहा रेलवे की अर्थ व्यवस्था पर 1973-74 में काफी दबाव पड़ते रहे हैं और इन दबावों के कारणों पर उन्होंने अपने भाषण में काफी रोशनी डाली है। चालू वर्ष में रेलवे की वित्त व्यवस्था का साधारण बजट पर, अनुमान है, लगभग 109 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

17. केन्द्रीय बजट की अतिरिक्त व अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और घाटे को न्यूनतम स्तर से ज्यादा न बढ़ने देने के लिए अतिरिक्त स्रोतों को जुटाने व खर्च को कम करने के दोनों कार्यों के लिए गंभीर प्रयत्न किये गये हैं। इस साल केंद्र को बाजार से ऋण लेने पर निवल 472 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे हालांकि बजट में 326 करोड़ रखे गये थे। विभिन्न मंत्रालयों के खर्च की आवश्यकताओं की बड़े ध्यान से समीक्षा की गयी और यह पता लगाया गया कि उनके प्रशासनिक व विकास-भिन्न खर्चों में कहां कहां बचत की जा सकती है। साधनों को ध्यान में रखते हुए, आयोजन के कुल खर्चों की भी, खास तौर से ऐसी योजनाओं के बारे में जो आयोजना की बुनियादी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, समीक्षा की गयी।

18. इन सब कोशिशों के बावजूद, इस साल के अन्त में 650 करोड़ रुपये का घाटा होगा। घाटे की अर्थ व्यवस्था के हानिकर प्रभावों के बारे में हमें गहरी चिन्ता है। लेकिन कोई भी सरकार अधिकांश जनता की कठिनाइयों और मुसीबतों को कम करने की अपनी जिम्मेवारी की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसी जिम्मेवारी की वजह से इतना बड़ा घाटा उठाना जरूरी हो गया।

#### बजट अनुमान 1974-75

19. अगला वित्तीय वर्ष पांचवीं आयोजना का पहला साल है। स्पष्ट है कि आयोजना के बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी लगाने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना एक जरूरी शर्त है। इसके साथ साथ साधारण आर्थिक स्थिति आवश्यक वित्तीय साधनों को जुटाने के काम को कठिन बना देती है। पिछले दो वर्षों में कीमतों के तेजी से बढ़ने के कारण गैर-विकास खर्च, खास तौर से वेतन व भत्ते पर खर्च, भारी मात्रा में बढ़ गया है जिससे विकास कार्यों के लिए बाकी बची धन राशि में कमी हो गयी है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन लगातार मंद रहने के कारण इसका राजस्व बढ़ोतरी पर असर पड़ा। 1974-75 का बजट बनते समय हमारे लिए इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि तेल संकट और विदेशों से मंगायी जाने वाली बहुत सी चीजों के बहुत ऊंचे दामों का हमारे भुगतान सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेशों से कौन कौन सी चीजों का आयात करना है तथा खेती की पैदावार व औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी होने से सरकार के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि वर्तमान परिस्थिति में अनिश्चय

व चिन्ता के अनेक कारण मौजूद हैं लेकिन मेरी धारणा है कि तात्कालिक समस्याओं की चिन्ता करते समय दीर्घ अवधि वाले विकास के लक्ष्य हमारी आँखों से ओझल नहीं होने चाहिए। चरना हम खुद ही मान खा जाने वाले काम कर रहे होंगे। मेरे विचार में मौजूदा घटनाओं से विकास के कार्यक्रमों का ठोस होना माबित हो गया है। देश की औद्योगिक व ऊर्जा की बुनियाद को मजबूत बनाने में इन कार्यक्रमों का सफल होना बहुत जरूरी है।

20. 1974-75 के बजट में आयोजना के लिए 2966 करोड़ रुपयों के कुल खर्च की व्यवस्था की गयी है। इसमें से 911 करोड़ रुपये राज्यों व संघ क्षेत्रों की आयोजना की सहायता के लिए और 2055 करोड़ रुपये केन्द्रीय आयोजना के लिए रखे गये हैं। इस व्यवस्था से दो परस्पर विरोधी बातों अर्थात् घाटे को कम से कम रखने और उत्पादन की रफ्तार बनाये रखने के बीच सन्तुलन रखा गया है जो कि एक कठिन काम है। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखा गया है कि ऐसी औद्योगिक व खेती की योजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय जो अर्थ व्यवस्था के भावी विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें पांचवीं आयोजना के पहलव दो वर्षों में पूरा किया जाना है जिसमें लगायी गयी पंजी में अर्थ-व्यवस्था को आयोजना की अवधि में काफी शुरू से ही लाभ पहुंचने लगे।

21. तेल की मौजूदा कमी और इससे पैदा होने वाले ऊर्जा संकट पे वाणिज्यिक ऊर्जा के अत्यन्त विविष्ट स्रोत के रूप में कोयले का महत्व बढ़ गया है। इसलिए 1974-75 के बजट में कोयले के उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है और इस काम के लिए 97 करोड़ पये रखे गये हैं। दूसरे शब्दों में कोयले पर खर्च पिछले वर्ष में 24 करोड़ पयों की व्यवस्था की तुलना में चार गुना बढ़ा दिया गया है। मैं अपने भाषण में आगे कुछेक सम्बन्धी उपायों का ब्योरा दूंगा जिनका उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा के स्रोत के प में तेल के बदले कोयले का इस्तेमाल शुरू करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।

22. हमारे आर्थिक विकास में इस्पात का महत्व भी कुछ कम नहीं है। इस्पात आसानी से मिल सकता है या नहीं इस बात का प्रभाव व्यापक रूप से न केवल औद्योगिक विकास की दर पर पड़ता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति में हम कितने सक्षम हैं, इस पर भी पड़ता है। इन सब कारणों से इस्पात के उत्पादन के लिए बजट में 162 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। अगर इसमें इस उद्योग के उपलब्ध साधनों को जोड़ दिया जाय तो कुल व्यवस्था लगभग 276 करोड़ रुपये की हो जाती है जो इस साल उपलब्ध कुल 201 करोड़ रुपयों से 75 करोड़ रुपये ज्यादा है।

23. आयात द्वारा अलोह धातुओं की सप्लाई पर देश को कम निर्भर बने रखने के लिए जितना तेजी से हो सके देशी स्रोतों का और ज्यादा विकास करना जरूरी है। इसके अनुसार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए 1974-75 के बजट में 75 करोड़ पयों की व्यवस्था की जा रही है। इस साल इस कार्य के लिए 56 करोड़ रुपये रखे गये थे।

24. यातायात की हमारी अर्थ-व्यवस्था में रेलों के प्रमुख स्थान को ध्यान में रखते हुए हमने सुनिश्चित किया है कि रेलों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध रहे। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, रेलों के क्षेत्र में गंभीर आर्थिक कठिनाइयां आ गयी हैं और उनकी अपनी आय से ऐसी आयोजना का खर्च पूरा नहीं हो सकेगा जिससे कि हमारी

अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसलिए मैंने रेलों को दी जाने वाली बजट की सहायता में पर्याप्त वृद्धि कर अगले वर्ष के लिए चालू वर्ष के 181 करोड़ रुपये की तुलना में 342 करोड़ रुपये रखे हैं।

25. उद्योग और खेती दोनों के उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली चीजों में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षों में बिजली की कटौती होते रहने से हमारी अर्थव्यवस्था जैसे अग्रगं होती गयी और इससे हमारी बिजली पैदा करने की क्षमता को तुरंत आगे बढ़ाने व मौजूदा बिजली कारखानों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने की जरूरत उभर कर सामने आ गयी है। पांचवीं आयोजना में बिजली बनाने की क्षमता को आयोजना के अन्त तक बढ़ा कर 330 लाख किलोवाट कर देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी कोशिश है कि जिन प्रयोजनाओं पर निर्माण का काम हो रहा है उन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाय व बिजली की ऐसी नई योजनाओं को शुरू किया जाय जो जल्दी ही पूरा हो सकती हों व जिनसे तुरन्त बिजली मिल सकती हो। गांवों की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर जितना जोर दिया जाय उतना कम है। हालांकि गांवों में बिजली पहुंचाने की अधिकांश योजनाएं राज्य आयोजना के क्षेत्र में आती हैं, इस मद को विशेष मद मानते हुए, मैं राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए 790 करोड़ रुपये की दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त ग्राम्य बिजलीकरण निगम के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूं। 1974-75 में बिजली के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कुल बजट व्यवस्था 121 करोड़ रुपये की होगी।

26. उर्वरकों में मौजूदा कमी और विदेशों से इन्हें मंगाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अगले वर्ष की आयोजना का जोर मौजूदा कारखानों की स्थापित क्षमता से ज्यादा उत्पादन हासिल करना व जिन आयोजनाओं पर काम हो रहा है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने पर है। बजट में इस क्षेत्र के लिये चालू वर्ष के 94 करोड़ रुपये की अपेक्षा 163 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो एक पर्याप्त वृद्धि है।

27. हालांकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधन जुटाने की हर कोशिश की गयी है, लेकिन खेती के क्षेत्र की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की गयी है। खेती के कार्यक्रमों बजट की सहायता के तौर पर हम 246 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। खेती की पैदावार की घटती व बढ़ती का राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर, कोमतों, औद्योगिक उत्पादन, भुगतान सन्तुलन और आमदनी के वितरण पर महत्वपूर्ण असर होता है। इसलिए खेती की पैदावार की बढ़ोतरी हम धन की कमी से रोकवट नहीं आने देंगे। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में हमने छोटे किसानों की योजनाएं, आदिवासी क्षेत्रों के विकास, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, संस्थागत ऋणों, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम व प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रम जैसी खेती की जो विभिन्न योजनाएं शुरू की, वह सन्तोषजनक रीति से प्रगति कर रही है।

28. सीमित साधनों के अन्दर-अन्दर और विकास के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मैंने इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन, समाज-कल्याण व आवास जैसी समाज सेवाओं के लिए अधिक धन राशि नियत की जाय। पहले की आयोजनाओं में सार्वजनिक उपयोग की कम से कम जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था की जाती रही उससे आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, इसका मुख्य कारण सम्बन्धित कार्यक्रमों को उचित प्राथमिकता

न दिया जाना और सुविधाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ सुनियोजित नहीं किया जाना था। सम्मानित सदस्य जानते हैं कि पांचवी आयोजना के मसीदे में न्यूनतम आवश्यकताओं के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है जिससे प्रारम्भिक शिक्षा, गांवों में स्वास्थ्य, पीन के पानी, गन्दी बस्तियों में सफाई, देहातों में सड़कें व गांवों में बिजली पहुंचाने के काम के रूप में न्यूनतम सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि राज्यों की सरकारें इस कार्यक्रम के लिए नियत की गयी राशि का कारगर ढंग से इस्तेमाल करेंगी।

29. बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए कुल व्यवस्था 2136 करोड़ रुपयों की होगी जिसमें संघ क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 81 करोड़ रुपये शामिल हैं किन्तु राज्यों की आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली 830 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय आयोजना के खर्च को पूरा करने के लिए बजट के अतिरिक्त 574 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। 1974-75 के लिए राज्यों की आयोजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस तरह 1973-74 के 4364 करोड़ रुपयों की तुलना में 1974-75 में आयोजना पर कुल खर्च 4769 करोड़ रुपया होगा।

30. हमने आयोजना में और अधिक खर्च करने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है जिससे हम तेजी से गरीबी हटाने व आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के दोहरे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। फिर भी मेरी धारणा है कि आयोजना में लगायी जाने वाली पूंजी से आशा के अनुरूप परिणाम तभी निकल सकते हैं जब आयोजना को दक्षता से कार्यान्वित किया जाय और उत्पादन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग, चाहे वह प्रबन्ध करने वाले हों अथवा श्रमिक हों समाज के प्रति अपनी व्यापक जिम्मेदारियों को महसूस करें। अगर आयोजना के लक्ष्य तक पहुंचना है तो यह नितान्त आवश्यक कि औद्योगिक सम्बन्ध, विशेष रूप से बुनियादी क्षेत्रों में सन्तोषजनक बने रहें। मुद्रा नीतियों व राजस्व नीतियों का उद्देश्य भी आयोजना के लक्ष्यों को पूरा करना ही होना चाहिए। साधनों का नियतन करने, प्रायोजनाओं व कार्यक्रमों का ठीक-ठीक चुनाव करने और उनका क्रम निर्धारण करने और कार्यक्रमों की सावधानी पूर्वक देख रेख करने में प्रभावपूर्ण प्रबन्ध-तकनीक को अपना कर इन नीतियों को पुष्ट करना होगा। सरकारी खर्च के कार्यक्रमों की उत्पादनशीलता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है अगर खर्च की रफ्तार पर सतत ध्यान रखा जाए जिससे समय रहते ही उसमें उचित सुधार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त कार्यक्रमों से जिस लाभ की आशा है, वह पूरा मिल सके। यह तभी हो सकता है जब वित्तीय नियन्त्रण व हिसाब किताब रखने की व्यवस्था को और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी को एक साथ मिला दिया जाय। उसके लिए हम लोग वित्तीय प्रणाली के ढाँचे में कुछ अवल बदल करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि निर्णय लेने के अधिकार व अच्छे परिणाम निकालने की जिम्मेवारी दोनों में आपस में तालमेल बना रहे।

31. लेखा नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा खाता रखने का जो नया बर्गीकरण निर्धारित किया गया है उससे सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों व कार्यक्रमों की जानकारी ज्यादा अर्थपूर्ण तरीके से होती है। इसी नये बर्गीकरण के आधार पर बजट तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे कार्यों के अनुसार बजट बनाने की प्रणाली को, जो पहले से ही प्रचलित है, और अधिक बढ़ावा मिलेगा और साधनों के नियतन की उपयोगिता व उससे मिलने वाले लाभ को आंकने के लिए इस तरीके का कारगर इस्तेमाल किया जायगा।



32. रक्षा पर कुल खर्च के तौर पर 1915 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिसमें तीसरे बेटन आयोग की सिफारिशों के कारण आवश्यक अतिरिक्त राशि शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा की विशाल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा खर्च को कम रखना सम्भव नहीं हो सका।

33. जहाँ तक साधनों का सम्बन्ध है हमें ऊर्जा मंदक के कारण राजस्व पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखना है हालांकि इस समय निश्चयपूर्वक इसके प्रभाव को आंका नहीं जा सकता। इस तत्व को ध्यान में रख कर हमने उत्पादन-गुल्क व सीमा-गुल्क की वृद्धि में कुछ कमी होने का अनुमान कर लिया है। इन दोनों साधनों से संशोधित अनुमान के अनुसार 1973-74 के 3608 करोड़ रुपयों की तुलना में 1974-75 में 3769 करोड़ रुपयों की आय का अनुमान है। 1973-74 (संशोधित अनुमान) के 1354 करोड़ रुपयों की तुलना में प्रत्यक्ष करों से 1423 करोड़ रुपयों की आय का अनुमान किया गया है।

34. छोटी बचतों से धनराशि मिलने में सन्तोषजनक प्रगति रही और 1974-75 में इससे 360 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान है। बाजार ऋण से निवल आय रूप में 498 करोड़ रुपयों के मिलने का अनुमान है जो 1973-74 से कुछ अधिक है।

35. खर्च के लिए सारी व्यवस्था तथा स्रोतों से अनुमानित आय को देखते हुए करों की मौजूदा दरों से बजट में पड़ने वाला अन्तर 311 करोड़ रुपयों का होगा। सदन स्वभावतः यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि किम तरह मैं इस अन्तर को पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अब इस विषय पर आता हूँ।

36. मैं सबसे पहले प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किए गए प्रस्तावों को शुरू करता हूँ। सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने इन करों के बारे में अनेक सिफारिशों की थीं। इनमें से बहुत सी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। कुछ अन्य सिफारिशों को लागू करने के उपबन्ध कराधान नियम (संशोधन) विधेयक 1973 में शामिल हैं। इस विधेयक पर इस सदन की प्रवर समिति विचार कर रही है। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सिफारिश का सम्बन्ध करों की दरों में कमी करने से है। समिति ने यह राय जाहिर की है कि कर छिपाने का सबसे पहला और मुख्य कारण है करों की ऊँची दरें, क्योंकि इन्हीं दरों के कारण कर का छिपाना लाभदायक व आकर्षक हो जाता है हालांकि इसमें अनेक जोखिम बने रहते हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि आयकर की दर की अधिकतम सीमा जिसमें अभिभार भी शामिल है, 97.75 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटा कर 75 प्रतिशत कर दी जाए। इसके साथ साथ बिचले व निचले स्तर पर कर की दरों में कमी की जानी चाहिए। समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी। इसके अनुसार मैं निजी आय के सभी स्तरों पर कर कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। कर की प्रस्तावित दरों के अन्तर्गत 6,000 रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाएगा। 70,000 रुपये से ऊपर की आमदनी पर बुनियादी आयकर की सीमान्तिक दर 70 प्रतिशत होगी। जिन अविभक्त हिन्दू परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्वतंत्र आय वाला हो और उस व्यक्ति की आय छूट की न्यूनतम सीमा से ज्यादा हो तब उस परिवार पर 50,000 रुपये से ज्यादा आय होने पर 70 प्रतिशत की सीमान्तिक दर लगेगी। निगम-भिन्न करदाताओं की सभी श्रेणियों के मामले में अभिभार की दर घटा कर 10 प्रतिशत की एक समान दर पर ले आयी जाएगी। आयकर व अभिभार का कुल भार व्यक्तियों और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में कर योग्य आय के सबसे ऊँचे खण्ड पर 77 प्रतिशत होगा।

37. निजी आय पर करों में कमी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जरूरी नहीं समझता कि भारतीय या विदेशी कम्पनियों को तकनीकी जानकारी या तकनीकी सेवा देने से निगम-भिन्न कर-दाताओं को जो आमदनी होती है उस पर कर लगाने समय तरजीही व्यवहार को जारी रखा जाए। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में दी जाने वाली मौजूदा रियायत को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

38. आय की असमानताओं व सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में राजस्व प्रणाली का असर कम न हो जाये इसे सुनिश्चित करने के लिये मैं ऐसे व्यक्तियों व अविभक्त हिन्दू परिवारों पर जहां किसी भी सदस्य के पास 1,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति नहीं है। 5,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति के खण्डों पर धन-कर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक के खण्ड पर धन-कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत व 10,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक के खण्ड पर 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी जिन ऐसे हिन्दू अविभक्त परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति है वहां पहले 5,00,000 रुपये के खण्ड पर धन-कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत व 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक के खण्ड पर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी।

39. मैं धन-कर अधिनियम के अधीन मिलने वाली मौजूदा रियायतों को युक्ति संगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। फार्म-हाउस के सम्बन्ध में अलग से दी जाने वाली छूट को भी वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि कर देने वालों को यह छूट रहेगी कि वे 1,00,000 रुपये की मौजूदा सीमा के अन्दर अन्दर एक फार्म हाउस या किसी एक और मकान के सम्बन्ध में छूट मांग सकते हैं। खेती की जमीन पर दी जाने वाली छूट विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मिलने वाली छूट से जोड़ दी जाएगी जिससे खेती की जमीन व विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के बारे में कुल छूट 1,50,000 रुपयों तक सीमित हो जाएगी। इस समय कर देने वाले को उसकी बीमा पालिसी के पूरा होने के पहले मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं देना होता। इसी तरह किसी भी एन्यूटी में, जो एक मुश्त अनुदान में बदली नहीं जा सकती, करदाता को इसी तरह की छूट मिली हुई है। कुछ लोगों ने ज्यादा भारी राशि की एक प्रीमियम वाली पालिसी लेकर इस छूट का अनुचित लाभ उठाया है। मैं इन उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। जिससे पूरी छूट बीमों की उस धन राशि के बारे में ही उपलब्ध होगी जहां 10 साल या उससे ज्यादा अवधि तक प्रीमियम दिया गया होगा। जहां तक एन्यूटियों का सम्बन्ध है, मैं राशिकृत न की जा सकने वाली एन्यूटी पर से इस छूट को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। अगर इन एन्यूटियों को करदाता ने खुद ही या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ ही संविदा के आधीन खरीद लिया है।

40. धन-कर अधिनियम में होने वाले परिवर्तनों से पूरे साल में लगभग 9.5 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 1975-76 के वित्तीय वर्ष में प्राप्त होंगे। निजी आय पर आयकर की दरों के घट जाने से सामान्यतः पूरे साल में 60 करोड़ रुपयों व 1974-75 के वित्तीय वर्ष में 36 करोड़ रुपयों का घाटा होना चाहिए था लेकिन मैं बजट के निमित्त इस घाटे को हिसाब में नहीं रख रहा हूं क्योंकि भले उम्मीद है कि करों की दरों के कम कर दिए जाने से ज्यादा कर मिलने लगेगा और सभी करदाता अपनी असली आमदनी दिखाने लगेंगे।

41. रजिस्टर्ड फर्मों पर इस समय दो अधिभार लगे हुए हैं। मैं ऐसी फर्मों द्वारा दिये जाने वाले साधारण अधिभार को बुनियादी आयकर में मिला देने और 10 प्रतिशत की एक समान दर पर एक ही सर टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। व्यवसायिक फर्मों व दूसरी फर्मों के मामले में बुनियादी आय कर के सम्बन्ध में उनकी देनदारी को लगभग मौजूदा स्तर पर बनाये रखने के लिये मैं फर्मों के बारे में दो दर अनुसूचियाँ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

42. 1971-72 के अपने बजट भाषण में मैंने 31 मई 1974 के बाद हासिल किये जाने वाले जहाजों या स्थापित की गई मशीनरी और संयंत्रों के बारे में विकास-छूट को वापस लेने के सरकार के इरादे की सूचना दी थी। ऐसा लगता है कि हमारे उद्योग कुछ मामलों में संयंत्र व मशीनरी को नियत समय के भीतर विदेशी व देशी दोनों निर्माताओं से हासिल नहीं कर पाये जिससे कुछ औद्योगिक प्रायोजनाएं जो सामान्यतः 31 मई 1974 के पहले पूरी हो जानी थीं, नियत समय के भीतर नहीं पूरी हो सकेंगी। इसके लिए अनेक अप्रत्याशित कारण हो सकते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का होना, कच्चे माल या महत्वपूर्ण कच्चे माल के बारे में देशी निर्माताओं का आयात पर निर्भर रहना, माल लाने के लिए जहाजों के मिलने में कठिनाई, बिजली सप्लाई में कमी आदि आदि। ऐसी वशा में राहत दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इस बात के निश्चित प्रमाण हों कि मशीनरी व संयंत्र खरीदने के संबंध में 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही कर दिये गये थे, मैं एक और साल के लिए विकास छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यह छूट 31 मई 1975 तक हासिल किये जाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में भी प्राप्त होगी अगर इन जहाजों की खरीद के संबंध में 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही कर लिये गये होंगे।

43. पेट्रोलेियम के उत्पादनों में भारी कमी के कारण एक अप्रत्याशित संकट आ गया है जिसके फलस्वरूप उद्योगों को ऊर्जा के दूसरे स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। इसलिए मैं कोयले से चलने वाले वायलरों पर और तेल से चलने वाले वायलरों को कोयले से चलने वाले वायलरों में बदलने के लिए 1 जून 1975 से पहले लगाया जाने वाली मशीनरी या संयंत्र पर विकास छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

44. वेतन पाने वाले करदाताओं के मामले में कर निर्धारण की पद्धति को आसान बनाने के लिये मैं यात्रा करने, किताबों, व्यवसाय पर कर और ट्यूटी पूरी करने में दिये गये खर्च के बारे में अलग अलग कटौती करने के बजाय 3500 रुपये की अधिकतम छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह कर्मचारियों की परिलब्धियों को अधिक वास्तविक आधार पर आंकने का प्रस्ताव करता हूं। मैं मेवा निवृत्ति लाभों पर लगने वाले करों में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन रिटायर होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी पर कोई आयकर नहीं लगेगा। जिन कर्मचारियों पर यह अधिनियम नहीं लागू होता उनके लिए ग्रेच्युटी पर छूट की सीमा 24,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये और 15 महीनों के वेतन से 20 महीने का वेतन कर दी गयी है।

45. राज्यों के वित्तीय निगमों को प्रारक्षित निधि का तेजी से निर्माण करने में सहायता देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि कर से मुक्त प्रारक्षित निधि में अन्तर्गत की जाने वाली राशि की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर चालू लाभ के 40 प्रतिशत तक कर दिया जाय।

46. खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास कार्य में अनेक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट व रजिस्टर्ड सोसायटियां काम कर रही हैं। यह ट्रस्ट व सोसायटियां खादी व ग्रामोद्योग आयोग के सीधे निर्देशन में प्रशंसनीय काम कर रही हैं। मैं इन सभी संस्थाओं को कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि ये संस्थाएं खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित हों।

47. कीमतें तय करने की नीतियों में परिवर्तन होने के कारण कुछ औद्योगिक कंपनियों को अपरिमित लाभ हो रहा है। मैं सोचता हूं कि इस मुनाफा का पर्याप्त हिस्सा सरकार को भी मिलना चाहिए। मैं इसलिए पूंजी के 15 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों

के बारे में सर टैक्स की दर को बढ़ा कर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से पूरे साल में 5 करोड़ रुपये मिलेंगे और यह 1975-76 में प्राप्त होंगे।

48. सारांश यह है कि प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिन प्रस्तावों का मैंने अभी जिक्र किया है उनसे अगले वित्तीय वर्ष में कर राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1975-76 के वित्तीय वर्ष में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 14.5 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

#### अप्रत्यक्ष कर

49. महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर आता हूँ।

50. पहले की तरह इस बार भी मुझे अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष करों, विशेषरूप से उत्पादन शुल्कों का अपेक्षाकृत अधिक सहारा लेना पड़ा है। चूंकि अन्य उपायों से धन जुटाने की गुंजाइश बहुत ही सीमित हो गयी है, इसलिए मेरे सामने दरअसल दो ही विकल्प हैं अर्थात् अप्रत्यक्ष करों से धन जुटाना और घाटे की वित्त-व्यवस्था करना, और मैं महसूस करता हूँ कि पहला विकल्प ही बेहतर है।

#### उत्पादन शुल्क

51. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में पहले मैं केवल केन्द्र के लिए साधन जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूंगा। सम्मानित सदस्यों को विदित है कि पिछले वर्ष उत्पादन-शुल्क लगायी जा सकने वाली सभी वस्तुओं पर उनकी कीमत के 20 प्रतिशत के बराबर सहायक उत्पादन-शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था की गयी थी। तब ये शुल्क केन्द्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास खास चीजों पर एक खास स्तर तक लगाये गये थे। मैं इस व्यवस्था को एक वर्ष और जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। हालांकि पिछले वर्ष चुनी गयी वस्तुओं पर शुल्क की प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं उस सूची में कुछ और चुनी हुई वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

52. संक्षेप में मेरा प्रस्ताव यह है कि अनिमित तम्बाकू, सिगरेट, स्मोकिंग मिक्सचर्स, प्लाइ-वुड और सीमेंट पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के दस प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय; रंगने के पदार्थों, आण्टीकल ब्लोचिंग एजेंटों, गैस, रबड़ की वस्तुओं और प्लास्टिक पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के बीस प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय; रोगनों और वानिषों पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के 33-1/3 प्रतिशत की दर से एड्रेटड वाटर, ग्लिसरीन, श्रुंगार और प्रसाधन सामग्री पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय। इन प्रस्तावों के जरिये और मौजूदा वस्तुओं पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्कों में जो फेर-बदल करने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ उनके परिणामस्वरूप, मुझे आशा है कि सहायक शुल्कों से एक वर्ष में 62.38 करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

53. इस्पात और अन्य धातुओं के मामले में, सहायक-शुल्क केवल देश के अन्दर होने वाले उत्पादन पर ही लगेंगे और पहले ही की तरह आयातों पर प्रतिस्तानुत्पन्नकारी शुल्क के रूप में लागू नहीं होंगे। मैं प्लास्टिक के मामले में भी एसी ही छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

54. जहां तक बुनियादी उत्पादन-शुल्कों का सम्बन्ध है, मेरे प्रस्तावों का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है और ये प्रस्ताव शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने, खपत को कम करने, आकस्मिक लाभों को बढ़ोदारी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व जुटाने के बहुत से उद्देश्यों को पूरा

करने के लिए तैयार किये गये हैं। नवम्बर, 1973 में, कच्चे तेल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होने और कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती होने के बाद, अनेक उपायों में से एक उपाय के रूप में, मोटर-स्प्रिट पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन-शुल्क को 1000 रुपये प्रति किलोलिटर से बढ़ा कर 2000 रुपये प्रति किलोलिटर कर दिया गया। पट्रोलियम से बनी कई अन्य चीजों की खपत पर रोक लगाने और उसमें किरायत करने की लगातार जरूरत को ध्यान में रखते हुये इन वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए मैं “स्पेशल बार्दलिंग प्वाइंट” स्पिरिटों, मेथनोल और पेट्रो-कैमिकल्स के काम आने वाले कच्चे नेफ्था, विभिन्न प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल होने वाले बन्जीन आदि, एस्फाल्ट, बिटुमेन, खनिज टर्पेन्टाइन तेल, मोग और ब्लेंड और गम्पाउन्ड लुब्रिकेटिंग आयल और ग्रीस पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्कों में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझ आशा है कि इन प्रस्तावों से पट्रोलियम वर्ग की चीजों से 22.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

55. पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के उत्पादन-शुल्कों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिये मैं मौजूदा वैकल्पिक दरों के स्थान पर मूल्यानुसार दरें लगाकर शुल्क-दरों को युक्ति-संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा विचार स्कूटरों, मोटर-साइकिलों, मोपेडों, आटो-रिक्शाओं और तीन पहियों वाली अन्य गाड़ियों पर मूल्यानुसार 9 प्रतिशत की एक समान दर लागू करने का है। उन मोटर गाड़ियों पर, जो आर० ए० सी० रेटिंग के अनुसार 16 अश्व शक्ति से अधिक की नहीं हैं, और जिनके अन्तर्गत यात्री-कारें और जीप आदि आजाती हैं, इस समय 13.33 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगता है। मैं बाड़ी वाली गाड़ियों के मामले में, इस दर को बढ़ा 20 प्रतिशत मूल्यानुसार, और अन्य गाड़ियों के मामले में, जो ड्राइव-अव चेसिस के रूप में निकासी की गयी हों, इस दर को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। बड़े आकार वाली गाड़ियों पर 40 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगेगा।

56. वाणिज्यिक गाड़ियों को यह लाभ प्राप्त है कि उन पर रियायती ‘मातानुसार’ दरें लागू होती हैं जो कुछ वर्ष पहले निर्धारित की गई थीं। मैं इन दरों को समाप्त करने और 12½ प्रतिशत की एक-समान मूल्यानुसार दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस तरह से, कुछ अतिरिक्त-भारी गाड़ियों को, जो इस समय टैरिफ-दर से शुल्क दे रही हैं, 2½ प्रतिशत का प्रासंगिक लाभ मिल जायेगा। लेकिन मेरा विचार ट्रैक्टरों और ट्रैलरों पर लगने वाली मौजूदा दर में परिवर्तन करने का नहीं है।

57. मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 16.25 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

58. सरकार के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अंग के रूप में, मैं समाज के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध लोगों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर अंकुश लगाने के लिये कुछ प्रस्ताव करता हूँ। रेफ्रिजरेटोर्स, एयर-कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग मशीनों, उपकरणों और उनके हिस्सों पर लगने वाले शुल्क की वर्तमान दरों में कुछ मौजूदा छूटों के सम्बन्ध में कुछ फेर बदल सहित, वृद्धि की जा रही है। लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेजों, प्लांटों और कारखानों पर लागू मौजूदा रियायती दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अनुमान है कि इन परिवर्तनों से एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

59. टेलीविजन सेटों के कुछ निर्माता विज्ञापनों में जनता से केन्द्रीय सरकार का बजट आने से पहले “टेलीविजन सेट खरीदें” अनुरोध कर हम सभी को उकसाते रहे। इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के सटीक ठहरने पर उनकी सराहना करते हुये मैं टेलीविजन सेटों के मूल्यानुसार

शुल्क की दर को 10 तिशत में बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। एक्सटेंडिड प्लेइंग रेकार्डों को भी शुल्क लगने वाली चीजों की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप धनिकों के लिये मनोरंजन अधिक महंगा हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि कम सुविधा प्राप्त लोगों को संगीत, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन अधिक बड़े पैमाने पर और कम खर्च पर उपलब्ध हों और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, मैं अब औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले और उपोक्तियों को अधिक से अधिक 225 रुपये तक की कीमत पर बेचे जाने वाले सभी रेडियो सेटों को पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुमान है कि इन उपायों से 1.20 करोड़ रुपये का निवल राजस्व प्राप्त होगा।

60. मैं विभिन्न किस्मों के सूती कपड़े पर, जिसमें सूत भी शामिल है, लगने वाले शुल्क की दरों में, राज्यों के लिये साधन जुटाने के सीमित उद्देश्य की पूर्ति को छोड़कर, कोई प्रमुख परिवर्तन करने से बचता रहा हूँ। शुल्क की मौजूदा दरें 'मात्रानुसार' हैं और ये 1969 में निर्धारित की गई थीं जब कि यह उद्योग कठिनाइयों से फंसा हुआ था। इसलिये इनमें परिवर्तन करने की स्पष्ट जरूरत है, खास तौर पर इसलिये कि इस बीच इस उद्योग की स्थिति सुधर गयी है। चूंकि सूती कपड़ा ग्राम इस्तेमाल की चीज है, इसलिये मैं इस बार में काफी सतर्क हूँ कि कुछ किस्मों के सूत और कपड़े के शुल्क की दरों में वृद्धि करने में धीरज रखने की आवश्यकता है। इसलिये मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध केवल सुपर-फाइन, फाइन, और मीडियम-ए कपड़े से है, जिन पर सर्मोराईजिंग/थ्रिफ-प्रूफिंग सेन्कोराईजिंग जैसी परिष्कृत प्रक्रियाएं की जाती हैं। सूत के मामले में, केवल ऊंचे काउंट वाले सूत के शुल्कों में वृद्धि की गयी है। लेकिन मैंने 'स्टेट-रीलड हैंक' के सूत के सम्बन्ध में, जिसका इस्तेमाल अधिकांशतः हथकरघा बुनकरों द्वारा किया जाता है, इस समय दी जाने वाली छूटों और रियायतों को नहीं हुआ है। मैंने कुछ छूटों और चक्रवृद्धि शुल्क दरों को भी युक्तिसंगत बनाया है। अनुमान है कि सूत और सूती कपड़े से सम्बन्धित इन उपायों से 22.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

61. दरों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में, जिससे राजस्व भी प्राप्त होगा, मैं पोलीएस्टर रेशे पर लगने वाले शुल्क की दो मौजूदा दरों को बढ़ा कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एक ही दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। पोलीएस्टर फिलामेंट धागे के विभिन्न डेनियर वर्गों पर लगने वाली मौजूदा दरों में उपयुक्त वृद्धि करने और इसके अनुरूप स्टेपल फाइबर स्पन यार्न और कुछ किस्मों के मिश्रित धागे की शुल्क-दरों को संशोधित करने और रेसिन-बाइंडेड स्लेंगवूल के शुल्क की दरों में वृद्धि करने के भी प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों से 13.99 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

62. लोहे और इस्पात के मामले में मैं पिग आयरन, स्टील इंगोट और बिजली की भट्टी से तैयार वस्तुओं और स्टील इंगोट के ऐसे टुकड़ों से, जिनका शुल्क चुका दिया गया हो, बनी वस्तुओं से सम्बन्धित कुछ छूटों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप 7.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

63. विभिन्न श्रेणियों के कागज और गत्ते के शुल्क की दरें 'मात्रानुसार' हैं और उनमें समय समय पर संशोधन करने की जरूरत पड़ती रहती है। मैं कागज और गत्त के शुल्कों की मौजूदा दरों में उपयुक्त वृद्धि करने का और इसके अलावा कुछ छूटों और वर्गीकरणों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन ग्राम किस्मों के छपाई और लिखने के कागज पर, जो अधिक से अधिक 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की 'ग्राम'-सीमा के अन्तर्गत आता है, लागू 15 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर, अखबारी कागज, हाथ के बने कागज और गत्ते के मामले में मिलने वाली पूरी छूट

और छोटे कागज-कारखानों और नव-स्थापित कारखानों के बारे में मौजूदा रियायतें जारी रहेंगी। इन उपायों में 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

64. राजस्व जुटाने के सोचे उपाय के रूप में, मैं सर्वेस एक्टिव एजेंट, कार्यालय-मशीनों, धातुओं के बने डिब्बों, रोलिंग बेयरिंगों, बेल्विंग इलेक्ट्रोडों, कोटेड एग्जिस्ट और प्राइडिंग व्हील्स, ड्राई बैटरियों, कुछ किस्मों के शीशे और शीशे की वस्तुओं, चीनी मिट्टी की चीजों और पोर्सलेन की चीजों की मौजूदा दरों में 5 प्रतिशत की मूलानुसार वृद्धि करने और इस प्रकार 20.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

65. साधन जुटाने के हमारे प्रावनों के एक अंग के रूप में मैं पहली बार टूथ पेस्ट (डेंटल क्रिम सहित), इलेक्ट्रिकल स्ट्राप्स और नेमिनेशन, विशिष्ट कटिंग औजारों, टेप और कैंसेट रेकार्डर्स, छली मिश्र धातु के स्थायी चुबकों, और फोटोग्राफी के सेंसिटाइज्ड कागज और गत्ते पर भिन्न भिन्न दरों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। सदस्यों को यह जान कर तसल्ली होगी कि जहाँ जल्दी है वहाँ छोटे निमाताओं को अनुचित छूट दी गयी है। इन नये शुल्कों से 8.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

66. उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कुछ अन्य प्रस्तावों से 3.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। उत्पादन-शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 1974-75 में राजस्व में 191.97 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि होगी जिसमें से 25.92 करोड़ रुपये राज्यों को और 166.05 करोड़ रुपये केन्द्र को प्राप्त होगा।

### सीमा-शुल्क

67. सीमा-शुल्कों के मामले में वस्तुओं की बढ़ती हुई विश्व-व्यापी कमी और विदेशों से मंगाये जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए, मेरे प्रस्ताव सीमान्तिक हैं। सारांश यह है कि मैं सहायक सीमा-शुल्कों को और उनसे सम्बन्धित छूटों को, मामूली संशोधन सहित, एक और वर्ष के लिए जारी रखना चाहता हूँ। इस समय ये शुल्क 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की तीन भिन्न भिन्न दरों से लगाये जाते हैं। मैं बीच के खण्ड पर लागू होने वाली दर को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस संशोधन से पूरे वर्ष में 16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी।

68. मेरे दूसरे, एक ही, प्रस्ताव का सम्बन्ध विहस्की, ब्रांडी, जिन और कुछ अन्य शराबों के बुनियादी शुल्क को 60 रुपये लिटर से बढ़ा कर 80 रुपये प्रति लिटर करने से है। हालांकि हमसे समाज के अपेक्षाकृत ऊँचे वर्ग को अपने मादक मनोरंजन के लिए कुछ ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे राजकोष के लिए कुछ राजस्व जुटाने में सहायता मिल जायगी।

69. उत्पादन-शुल्कों में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त शुल्कों में होने वाले परिवर्तनों सहित, आयात शुल्कों से प्रति वर्ष 20.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

70. सीमा-शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों को इकट्ठा लेने पर, राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद, केन्द्र को पूरे वर्ष में 186.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

### डाक और तार

71. अब मैं अपने सहयोगी संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि सदन को मालूम ही है, डाक की दरों में बढ़ती हुई लागत के साथ साथ वृद्धि नहीं हुई। मई-जून माह में बार बार

वृद्धि होने और बेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर भारी अतिरिक्त व्यय होने के कारण डाक शाखा का जो एक श्रम प्रधान प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान व्यय और अधिक बढ़ गया है। दूर-संचार शाखा में भी, संचालन लागत और विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की लागत में भी लगातार वृद्धि होती रही है। माइक्रो-वेव और को-एक्सियल प्रणालियों जैसे उच्च फ्रेड के साधनों की व्यवस्था करने ट्रंक टेलीफोन सेवा में सुधार करने, टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और ट्रंक डायलिंग और टेलीप्रिंटर सुविधाओं का विस्तार करने के लिए डाक-तार विभाग के सभी विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी बातों के कारण डाक-तार विभाग की डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन की दरों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। बजट-पत्रों के साथ एक शापन बांटा जा रहा है जिसमें डाक-तार की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी दी गयी है। इसलिए मैं केवल अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा।

72. पोस्ट-कार्ड की कीमत को 10 पैसे से बढ़ा कर 15 पैसे कर देने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि के बाद भी इस विभाग को इस सेवा के संचालन पर प्रति वर्ष 2.43 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। लैटर-कार्डों की कीमत को 15 पैसे से बढ़ा कर 20 पैसे और 15 ग्राम तक के वजन वाले लिफाफों की कीमत 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे कर देने का प्रस्ताव है। रजिस्ट्रेशन फीस को 1 रुपये से बढ़ा कर 1.25 रुपये और प्रत्येक 400 ग्राम के लिए पार्सल की दर को 1 रुपये से बढ़ा कर प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 1.50 रुपये किया जा रहा है। वी० पी० पी० की डाक-दर और बिजनेस-रिप्लाई पर्मिट की दरों में संशोधन किया जा रहा है। 'सामान्य' श्रेणी के 8 अथवा उससे कम शब्दों वाले प्रेम-भिन्न तार की न्यूनतम दर को 1.20 रुपये से बढ़ा कर 1.50 रुपये और 'एक्सप्रेस' श्रेणी के तार की दर को 2.40 रुपये से बढ़ा कर 3.00 रुपये किया जा रहा है। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए दर वही रहेगी जो पहले थी। टेलीफोन कनेक्शनों की 'मापित दर प्रणाली' और 'एक-समान दर प्रणाली' दोनों की दरों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। लेकिन एक तिमाही में मुफ्त कालों की संख्या को 250 से बढ़ा कर 300 कर दिया जायगा। 300 कालों के बाद की प्रत्येक अतिरिक्त काल की दर को 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे कर दिया जायगा। ट्रंक काल दरों के ढाँचे को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 100 से 1300 किलोमीटर तक के बीच के फासले के लिए ट्रंक काल की दर में वृद्धि होगी, लेकिन 20 किलोमीटर की दूरी तक के स्टेशनों के बीच की गयी कालों के सम्बन्ध में एक 'सामान्य' काल के लिए 25 पैसे का शुल्क लिया जायगा जब कि आजकल इन कालों का शुल्क 50 पैसे प्रति काल है।

73. दरों में किये गये इन संशोधनों से प्रति वर्ष 57.08 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ये परिवर्तन उन तारीखों से लागू किये जायेंगे जो संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किये जाने के बाद अधिसूचित की जायेंगी। 1974-75 के वित्तीय वर्ष में 42.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

74. डाक और तार विभाग के आन्तरिक साधनों का हिसाब लगाते समय इन परिवर्तनों के परिणामों पर ध्यान रखा गया है।

75. जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है, विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1974-75 में कुल मिलाकर 186 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। तदनुसार, बजट का 311 करोड़ रुपये का भाटा, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था, अब कम होकर 125 करोड़ रुपये रह जायगा।



76. अन्त में मैं फिर एक बार सदन का ध्यान विछने दो। वर्षों में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने यह दिखा दिया है कि कुछ घटनाएँ बजट के मूल अनुमानों को कितना ज्यादा उलट पुलट सकती हैं। अगले वर्ष में परिस्थितियों के अस्थिर रहने के अनेक कारण बने हुए हैं जो पहले कभी नहीं थे लेकिन इन कारणों का समाधान हमें तत्परता से ब अपने को ढालते हुए करना है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम इन अनिश्चितताओं के कारण अपने लक्ष्य को ओलल नहीं होने देंगे। इस समय हम जिन सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आखिरकार, उन्हें सामाजिक उद्देश्यों वाली विकासशील अर्थ व्यवस्था के ढांचे में ही हल किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह बजट इस दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है।

## Budget 1974-75

### Speech of Minister of Finance 28th February, 1974

Sir,

I rise to present the revised estimates for 1973-74 and the budget estimates for 1974-75.

2. This is the fourth regular budget of the Union Government which I have been privileged to present to this House. The principal concern of every Central budget has to be to strike a proper balance between the requirements of accelerated growth, stability, greater social justice and self-reliance. In the long run, these objectives are self-reinforcing. In the short run, however, a reconciliation of these objectives is not an easy task even under favourable conditions. During the last three years conditions have not been favourable; in fact they have been far from normal in many ways. In each of these years, we had to face new challenges of extraordinary dimensions. We have tried to meet those challenges to the best of our ability. I shall, however, readily admit that, because of unusually severe strains caused by a combination of certain national and international factors beyond our control, progress in achieving our objectives has fallen short of expectations.

3. I would like to state frankly that in the coming financial year the economy will be faced with even greater challenges. Its strength and adaptability will be severely tested. The steep rise in the price of crude oil and also some other commodities has turned the terms of trade sharply against us and has rendered our tasks exceptionally difficult. Recent developments must, however, be viewed in a wider historical perspective. Nowhere in the world has the process of social and economic change been smooth or free from ups and downs. I find no reason, therefore, to lose heart or to start questioning our basic goals and objectives. Our socio-economic objectives remain as relevant as before. Our commitment to our goals is as resolute as ever. We cannot give up the war against poverty, ignorance and disease because the going is more difficult than anticipated, though our tactics may need to be readjusted to changing circumstances.

#### THE STATE OF THE ECONOMY

4. As the House is aware, the Government has been deeply concerned about the acute inflationary pressures that have prevailed in the economy during the last two years. The measures that have been adopted to deal with these inflationary pressures are well known to the Honourable Members. It is a matter of deep regret to me that despite these measures prices have continued to rise. The House will appreciate that the pressure on prices was inevitable as a result

of the unsatisfactory performance in the field of agricultural production in two successive years, 1971-72 and 1972-73. The steep fall of 9.5 per cent in agricultural output in 1972-73 was bound to upset the delicate balance between demand and supply. Because of a much sharper increase in international prices, the substantial imports of foodgrains that we arranged were also unable to exercise a stabilising influence on domestic prices. Even with a more normal kharif crop in 1973, the pressure on prices has not abated in view of other inflationary forces at work in the economy.

5. It appears certain that the national income in 1973-74 will record a significant growth; this will help to neutralise the unsatisfactory behaviour of national income in the two previous years. It is, however, a matter of deep concern to us that in the Fourth Plan our overall rate of growth has been much lower than the Plan target. It is also a matter of deep regret that the upsurge in industrial production that was evident in 1972 was not sustained in 1973. The available indicators suggest that there was hardly any increase in the rate of growth of industrial production in 1973. It will be a major objective of our economic policy to revive the tempo of industrial activity in 1974. To secure an adequate rate of growth is the challenge that we face in the Fifth Five Year Plan.

6. As the House is aware, in order to supplement domestic supplies, Government imported significant quantities of foodgrains and vegetable oil from abroad during 1973-74. These imports were necessary for the well-being of the nation, but have naturally greatly inflated our import bill. Fortunately, our exports have grown at a satisfactory rate and, as a result, the deterioration in our balance of payments has been contained within manageable proportions. However, it is no use minimising the likely adverse effect on our balance of payments which will inevitably arise as a result of the steep increase in the prices of crude oil and of commodities like fertilizer and non-ferrous metals. In the long run, among the most important steps by which our economy can adjust to this massive structural shift in our terms of trade without affecting our growth prospects, is by replacing oil, wherever possible by other domestically available sources of energy, and by intensifying the programme for oil exploration. In this context, the highest priority attaches to securing a significant increase in the production of coal in the shortest possible time. Even so, a large increase in our import bill is inevitable, and this will necessitate a significant increase in our export earnings. The oil crisis, while no doubt adding to our difficulties, has already created new export opportunities in respect of products such as jute textiles, cotton textiles and leather goods. We must grasp this opportunity and do everything in our power to maximise our export earnings. A comprehensive review of our export prospects has been undertaken. This review will enable us to launch a well articulated programme for exploiting fully our export potential.

7. In my budget speech last year I had listed control of inflation, promotion of higher levels of savings and investment, greater viability of our external payments, and generation of new employment opportunities as the most pressing immediate tasks before the nation. The steep increase in prices in the last one year, the severe pressure on the balance of payments that will inevitably arise in the wake of higher prices of oil and other international commodities, and the stagnation of industrial production in 1973 have lent an added urgency to these tasks. The relatively poor performance of the economy last year should not give rise to a growing feeling of doubt, uncertainty and cynicism. We must combat these attitudes and preserve the people's faith in our democratic polity as an effective vehicle of social change.

#### REVISED ESTIMATES, 1973-74

8. The House will recall that the budget estimates for 1973-74 had envisaged a deficit of Rs. 87 crores. This excluded provision for expenditure arising out of the recommendations of the Third Pay Commission since the Commission's report was not available at the time of formulation of the budget proposals. It was anticipated that the acceptance of these recommendations would raise the budget deficit to a level substantially higher than Rs. 87 crores. However, subsequent events, largely an outgrowth of the steep fall in agricultural output in 1972-73, have led to a much greater deterioration in the budgetary position than was originally anticipated.

9. As Honourable Members are aware, extensive drought relief operations, started on account of the widespread and unprecedented drought in 1972-73, had to be continued to a large extent in 1973-74 also. At the peak of these operations 1,43,740 relief works were opened over the entire country and 93 lakhs of people were employed. It was hoped that with the onset of the monsoon in 1973-74, and increasing involvement of the labour force in agricultural operations, the

number of people employed on relief works would diminish appreciably. Unfortunately this did not happen. Consequently the Central Government had to continue massive assistance to State Governments on this account. Honourable Members will recall that a sum of Rs. 100 crores was provided in the current year's budget for this purpose. This provision proved to be wholly inadequate and had to be stepped up by another Rs. 220 crores.

10. In this connection I would invite the attention of Honourable Members to the observations of the Finance Commission regarding expenditure on relief for natural calamities. The Commission has urged that instead of incurring expenditure on relief on an *ad hoc* basis, provision should be made on a much larger scale for development of drought and flood-prone areas in the Fifth Plan, both in the State and Central sectors. Following these recommendations it has been decided to integrate these programmes with development plans to the extent possible.

11. Apart from larger assistance provided to State Governments for expenditure on natural calamities relief, provision for special assistance to States to meet gaps in their resources, and for specified projects, had also to be increased. The budget provided an amount of Rs. 188 crores for this purpose, and this will have to be stepped up by nearly Rs. 91 crores.

12. The Central exchequer had to bear other burdens as well. The expenditure on food subsidy will be higher than the provision of Rs. 130 crores by Rs. 121 crores despite some revision in the issue prices of foodgrains. This is essentially due to the high cost of imported foodgrains.

13. The direct impact of the price rise on Government spending arises from the increased quantum of dearness allowance provided to Government employees this year. Honourable Members will recall that in accepting the recommendations of the Third Pay Commission we had agreed to a liberalised formula for dearness allowance to enable low paid Government employees to get adequate compensation for the rise in the cost of living. On this basis, the four instalments of dearness allowance we have sanctioned will cost the exchequer nearly Rs. 100 crores.

14. The impact of the recommendations of the Third Pay Commission was estimated at Rs. 150 crores. This was a large commitment, particularly in the context of the difficult economic situation prevailing in the country, and was based on the expectation that we would accept most of the Commission's recommendations. We have in fact agreed to make some significant improvements in the Pay Commission's recommendations regarding the pay structure of Government employees; these improvements alone are likely to cost the exchequer Rs. 61 crores a year on a recurring, and Rs. 25 crores on non-recurring basis. The Government has stretched its resources to the utmost in order to meet the demands of its employees. I sincerely hope that they will appreciate this, and do their best to improve their efficiency and productivity.

15. On the receipts side, there have been shortfalls. The stagnation in production in a number of major sectors of industry, caused by shortage of raw materials and power cuts has adversely affected receipts from excise duties. Shortfall on this account is estimated to be Rs. 107 crores.

16. As the Railway Minister stated yesterday, the finances of the Railways in 1973-74 have been under considerable strain for reasons dealt with at length in his speech. The net additional impact of the financial working of the Railways on the general budget in the current year is expected to be around Rs. 109 crores.

17. In order to meet the additional and inescapable demands on the Central Budget, and to contain the deficit to the minimum Government had made serious efforts both to tap additional resources and to restrict expenditures. The net market borrowing by the Centre this year will amount to Rs. 472 crores, as against the Budget provision of Rs. 328 crores. The expenditure requirements of the various Ministries were carefully reviewed and savings were located in their administrative and other non-developmental expenditure. In view of the difficult resource position, a review of the Plan outlays was also undertaken, particularly in regard to schemes which were not vital to the core of the Plan.

18. Despite all these efforts, the year-end deficit will be of the order of Rs. 650 crores. We are deeply concerned about the deleterious effects of deficit financing. But no Government can overlook its obligation to alleviate the hardships and

sufferings of large sections of the people. It is this obligation that has rendered a larger deficit inescapable.

#### BUDGET ESTIMATES, 1974-75

19. The next financial year is the first year of the Fifth Plan. A significant step-up in the rate of investment is clearly an essential condition for the realisation of basic objectives of the Plan. At the same time, the general economic situation renders the task of raising the needed financial resources more difficult. The sharp rise in prices in the last two years has greatly increased non-developmental expenditure, particularly on pay and allowances, thereby reducing the surpluses for development. In addition, the continued sluggishness of industrial production has affected the growth of revenues. In framing the budget for 1974-75, we also have to take into account the likely impact of the oil crisis and very high prices of many imported commodities on the country's balance of payments, the pattern of imports, and the growth of agricultural and industrial output on government revenues. I would be the last to deny that there are many sources of uncertainty and anxiety in the present situation. Nevertheless, I am convinced that a legitimate concern with our immediate problems must not lead to a neglect of our long term growth objectives. That would be a self-defeating exercise. In my view, recent events have only further vindicated the soundness of a development strategy which must succeed in strengthening the country's industrial and energy base.

20. The Budget for 1974-75 provides for a total outlay of Rs. 2,966 crores for the Plan. Out of this Rs. 911 crores have been provided as assistance to State and Union Territories Plan, while the provision for the Central Plan is Rs. 2,055 crores. This provision represents a difficult compromise between two conflicting considerations, namely to keep deficit financing to the minimum and to keep the wheels of production moving. Particular care has been taken to make adequate provision for such industrial and agricultural schemes and projects as are essential for the future growth of the economy, and are likely to be completed in the first two years of the Fifth Plan, so that the economy derives the benefits from investments early enough in the Plan period.

21. The role of coal as the most important source of commercial energy has been underlined by the urgent shortage of oil and the resultant energy crisis. The development of coal has, therefore, been accorded very high priority in the budget for 1974-75. Rs. 97 crores have been earmarked for this purpose. In other words the outlay on coal has been increased four times as compared to the provision of Rs. 24 crores last year. Later in my speech, I shall outline certain fiscal measures which are designed to encourage industry to switch over, as early as possible, from the use of oil to coal as a source of energy.

22. No less critical is the role of steel in our economic development. The availability of steel has a major influence not only on the pace of industrial development, but also on the viability of our international payments. For all these reasons, the budgetary provision for steel production has been fixed at Rs. 162 crores. It one adds to this figure the internal resources available the total figure amounts to Rs. 276 crores, which is Rs. 75 crores more than the total of Rs. 201 crores available this year.

23. In order to reduce the country's acute dependence on imported supplies of non-ferrous metals, it is also necessary to push ahead with the development of domestic resources as fast as we can. Accordingly, a provision of Rs. 75 crores is being made in the budget for 1974-75 for the development of this vital sector. This is against Rs. 56 crores provided this year.

24. In view of the predominant role the railways play in our transport economy, we have ensured that adequate finances are provided for the development of railways. As Honourable Members are aware, the railways have run into serious financial difficulties and their own resources may not be sufficient to finance a Plan of an order which will meet the requirements of our economy. I have, therefore, considerably stepped up the budgetary support for the Railways to Rs. 342 crores next year, as against Rs. 181 crores in the current year.

25. Power is a vital input for both industry and agriculture. The power shortages that developed during recent years have had a crippling effect on the economy and have highlighted the urgent need for augmenting our generating capacity and improving the operational performance of existing plants. The Fifth Plan envisages that installed capacity of power generation will be stepped up to 33 million k.w. by the end of the Plan. The strategy is to expedite the completion of projects which are already under construction, and to go in for new thermal schemes which have short gestation periods. The importance of rural electrification in developing the rural economy can hardly be over-emphasised. Though many of the rural electrification schemes fall in the State

Plan sector, as a special case, I am providing Rs. 40 crores for the Rural Electrification Corporation over and above Rs. 780 crores of assistance provided to States for their Plans. The total budgetary provision for power in the Central Budget during 1974-75 will be Rs. 121 crores.

26. Considering the current shortage of fertilizers and difficulties in procuring these from abroad, the thrust of next year's Plan will be to maximise production from installed capacity and to speed up the implementation of projects already under way. The budget provides Rs. 163 crores for this sector as against Rs. 94 crores in the current year which is a substantial increase.

27. While every effort has been made to provide resources to stimulate industrial production, the requirements of the agricultural sector have not been ignored. We are providing Rs. 246 crores as budgetary support for agricultural programmes. The behaviour of agriculture has a crucial impact on the growth of national income, prices, industrial production, balance of payments and the distribution of income. Accordingly, we shall not allow paucity of resources to stand in the way of maximising our agricultural output. Honourable Members will be happy to note that various agricultural schemes which we have undertaken in the last few years such as schemes for small and marginal farmers, tribal development, development of hill areas, provision of institutional credits, drought-prone areas programmes, and the applied nutrition programme are making satisfactory progress.

28. Within the overall constraints of resources, and after meeting the minimum needs of the core sectors of development I have attempted to provide as large funds as possible for social services like education, health, family planning, social welfare and housing. The provisions made in earlier Plans for meeting minimum essential needs for social consumption did not achieve the desired results, mainly because related programmes were not given due priority, and an effective integration of facilities was not attempted. Honourable Members are aware that the draft Fifth Plan has provided for a National Programme of Minimum Needs to achieve a certain minimum level of social consumption in the form of elementary education, rural health, drinking water, provision for slum clearance, rural roads and rural electrification. I hope that the State Governments will be able to ensure effective utilisation of the resources allocated for this programme.

29. The total provision for the Central Plan in the Budget inclusive of Union Territory Plan of Rs. 81 crores will amount to Rs. 2,136 crores excluding Central assistance of Rs. 830 crores for the Plans of the States. In addition, extra budgetary resources for financing the Central Plan will amount to Rs. 574 crores. The resources for State Plans for 1974-75 will be of the order of Rs. 2,059 crores. Thus, the total Plan outlay during 1974-75 will amount to Rs. 4,769 crores as against Rs. 4,364 crores in 1973-74.

30. We have decided in favour of a larger Plan outlay to enable us to move faster towards the twin objectives of removal of poverty and attainment of economic self-reliance. I am however convinced that Plan investments can yield benefits on the scale anticipated only if the Plan is implemented efficiently and all the participants in the productive process—management and labour—accept the larger obligations they owe to the community. Maintenance of satisfactory industrial relations particularly in key sectors is absolutely essential if the Plan targets are to be achieved. Monetary and fiscal policies should also be directed towards the achievement of Plan objectives. These policies will have to be supplemented by the adoption of effective management techniques in the allocation of resources, proper selection and phasing of projects and programmes and close monitoring of programmes. The productivity of public expenditure programmes can be enhanced considerably if continuous attention is paid to the flow of expenditure so that appropriate corrective action is taken well in time to ensure that the benefits expected are fully realised. This can be achieved only if financial control and management accounting functions are dovetailed with the responsibility for execution of programmes. We are, therefore, contemplating some structural changes in the financial management system so as to match the authority for taking decisions with the responsibility for producing results.

31. The new accounting classification prescribed by the Comptroller and Auditor General reflects more meaningfully the functions, programmes and activities of the Government. The Budget is framed on the basis of this new classification. With this, Performance Budgeting, which is already in vogue, will, I believe, receive a further impetus and it will be made an effective instrument to measure the efficacy of the allocation of resources and the returns therefrom.

32. The outlay on Defence has been provided at Rs. 1,915 crores which includes the provision for additional funds required on account of the acceptance of the recommendations of the Third Pay Commission. Keeping in view the large requirements of national defence and security, the provision for Defence could not possibly be kept at any lower level.

33. On the side of resources, we have to reckon with the likely adverse impact of the energy crisis on revenues, though it is difficult to estimate the impact at this stage with any degree of certainty. As an allowance for this factor, we have assumed some deceleration in the growth of revenues from excise and customs. Together, these two sources are expected to yield Rs. 3,769 crores in 1974-75 as compared to Rs. 3,608 crores in 1973-74 according to the revised estimates. The estimated yield from direct taxes is Rs. 1,423 crores as against Rs. 1,354 crores in 1973-74 revised estimates.

34. The progress in small savings collections is gratifying and estimates for 1974-75 are placed at Rs. 360 crores. The estimated net receipts from market borrowings at Rs. 498 crores also show a marginal improvement over 1973-74.

35. Taking into account all the provisions for expenditure and the estimates of resources, the budgetary gap at existing rates of taxes will amount to Rs. 311 crores. The House will naturally be anxious to know as to how I propose to meet this gap. I now turn to this task.

#### DIRECT TAXES

36. I come first to the proposals in the field of direct taxes. As Honourable Members are aware, the Direct Taxes Enquiry Committee has made a number of recommendations in regard to direct taxes. Several of these recommendations have already been implemented. Provisions to give effect to some other recommendations are included in the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973 which is at present before a Select Committee of this House. One of the important recommendations of the Committee relates to reduction in the rates of taxes. The Committee has expressed the view that prevalence of high rates is the first and foremost reason for tax evasion, because this is what makes the evasion, in spite of attendant risks, profitable and attractive. The Committee has, accordingly, recommended that the maximum marginal rate of income-tax, including surcharge, should be brought down from its present level of 97.75 per cent to 75 per cent. Simultaneously, there should be a reduction in tax rates at the middle and lower levels. This recommendation of the Committee has been accepted by Government with minor modifications. I, accordingly propose to lower taxes at all levels of personal incomes. Under the proposed rate schedules, no income-tax will be payable by individuals or Hindu undivided families having income not exceeding Rs. 6,000. The marginal rate of basic income-tax will stand at 70 per cent on the income in the slab over Rs. 70,000. In the case of Hindu undivided families having at least one member with an independent total income exceeding the minimum exemption limit, the marginal rate of 70 per cent will be attracted at income levels over Rs. 50,000. The rate of surcharge will be reduced to a uniform level of 10 per cent in the case of all categories of non-corporate tax-payers. The combined incidence of income-tax and surcharge, in the case of individuals and Hindu undivided families, will stand at 77 per cent of the taxable income in the highest slab.

37. In view of the reduction in taxes on personal incomes, I do not think it is necessary to continue the preferential tax treatment in respect of incomes derived by non-corporate taxpayers through providing technical 'know-how' and technical services to Indian or foreign enterprises. I, accordingly, propose to withdraw the existing concession in this regard.

38. In order to ensure that the effectiveness of the fiscal instrument for reducing disparities in incomes and wealth is not impaired, I propose to increase the rates of wealth-tax on the slabs of net wealth over Rs. 5,00,000 in the case of individuals and Hindu undivided families, where no member has net wealth exceeding Rs. 1,00,000. The rate of wealth-tax on the slab of Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 will be increased from 2 per cent to 3 per cent, and on the slab of Rs. 10,00,001 to Rs. 15,00,000 from 3 per cent to 4 per cent. In the case of Hindu undivided families having at least one member with net wealth exceeding Rs. 1,00,000, the rate of wealth-tax on the first slab of Rs. 5,00,000 will be raised from 2 per cent to 3 per cent and on the slab of Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 from 3 per cent to 4 per cent.

39. I also propose to rationalise some of the exemptions available at present under the Wealth-tax Act. I propose to withdraw the separate exemption in

respect of farm houses. Taxpayers will, however, have the option to claim exemption in respect of one farm house, or one other house property within the existing limit of Rs. 1,00,000. Exemption in respect of agricultural land will be linked with the exemption in respect of specified financial assets, so that the total exemption in respect of agricultural land and specified financial assets will be limited to Rs. 1,50,000. At present, the value of the taxpayer's interest in insurance policies before their maturity is completely exempt from wealth-tax. A similar exemption is also available in respect of the taxpayer's right in any annuity which is not commutable into a lump sum grant. These exemptions have been exploited by certain individuals by taking out single premium policies of very large amounts. I propose to modify these provisions so that complete exemption will be available in respect of insurance monies only where premia have been paid over a period of 10 years or more. As regards annuities, I propose to withdraw the exemption in respect of non-commutable annuities if such annuities have been purchased by the taxpayer himself, or by any other person in pursuance of a contract with him.

40. The changes in the Wealth-tax Act will yield about Rs. 9.5 crores in a full year, which will accrue in the financial year 1975-76. The reduction in the rates of income-tax on personal incomes would ordinarily have resulted in a loss of about Rs. 60 crores in a full year and Rs. 36 crores in the financial year 1974-75. I am, however, not taking any loss into account for budgetary purposes as I expect that the reduction in the rates of taxes will lead to better tax compliance, and full disclosures of incomes by all taxpayers.

41. In the case of registered firms, two surcharges are presently levied. I propose to merge the ordinary surcharge payable by such firms with the basic income-tax, and specify only one surcharge at the uniform rate of 10 per cent. In order to retain the liability in respect of basic income-tax in the case of professional firms, as well as other firms at more or less the existing levels, I propose to prescribe two separate rate schedules in the case of such firms.

42. In my budget speech for 1971-72, I gave notice of Government's intention to withdraw the development rebate in respect of ships acquired or machinery and plant installed after May 31, 1974. It now appears that industry has in some cases not been able to secure timely delivery of plant and machinery both from foreign and indigenous manufacturers which has caused a setback to the timely completion of some of the industrial projects which would in the normal course have been completed before May 31, 1974. Several unforeseen factors are responsible for this, such as uncertainty prevailing in the international market, dependence of indigenous manufacturers on imports in respect of critical parts or raw materials, difficulties in the availability of shipping space power shortage etc. Relief is deserved in such cases, and I propose to extend the operation of the development rebate by one year in cases where there is conclusive evidence to show that contracts for purchase of machinery and plant were finalized before December 1, 1973. This extension will also be available in respect of ships acquired up to May 31, 1975, if the contracts for purchase were made before December 1, 1973.

43. The critical shortage of petroleum products has resulted in an unexpected crisis as a result of which industry has to be encouraged to switch over to other sources of energy. I, accordingly, propose to allow development rebate in respect of coal-fired boilers or any machinery or plant for converting oil-fired boilers to coal-fired boilers where these are installed before June 1, 1975.

44. In order to simplify the assessment procedure in the case of salaried taxpayers, I propose to substitute the separate deductions in respect of travelling, books, taxes on professions and expenditure incurred in the performance of duties by a standard deduction up to a maximum of Rs. 3,500. Simultaneously I propose to place the valuation of perquisites of employees on a more realistic basis. I also propose to liberalise the tax treatment of retirement benefits in certain directions. The retiring gratuities payable under the Payment of Gratuities Act, 1972 will be completely exempt from income-tax. In the case of employees not covered by that Act, the alternative ceiling limits on the exempted amount of gratuities will be raised from Rs. 24,000 to Rs. 30,000 and from 15 months' salary to 20 months' salary.

45. In order to enable State financial corporations to build up reserves at an accelerated pace, I propose to raise the ceiling limit in respect of amounts transferred to tax exempt reserves to 40 per cent of the current profits.

46. There are a large number of public charitable trusts and registered societies engaged in the development of khadi and village industries. These trusts and societies are doing commendable work under the direct supervision of the Khadi

and Village Industries Commission. I propose to exempt all such institutions from income-tax provided they are approved by the Khadi and Village Industries Commission.

47. As a result of the change in pricing policies, some of the industrial companies are making windfall profits. I feel that the exchequer should also secure a larger share of these profits. I, accordingly, propose to increase the rate of surtax from 30 per cent to 40 per cent in respect of chargeable profits of companies exceeding 15 per cent of the capital. This measure will yield Rs. 5 crores in a full year and this will accrue in 1975-76.

48. To sum up, in the field of direct taxes no effect is expected on tax revenues during the next financial year as a result of the proposals outlined by me. In the financial year 1975-76, there will be an addition of Rs. 14.5 crores as a result of these changes.

### INDIRECT TAXES

49. Sir, I will now move on to the proposals relating to indirect taxes.

50. As in the past, I have necessarily to rely more heavily on indirect taxes, particularly excise duties. The scope for raising resources from other measures having become severely limited, the choice before me has really been between raising indirect taxes and resorting to deficit financing and the former, I feel, is the better alternative.

### EXCISE DUTIES

51. Taking up Central Excises, I shall first deal with some important measures for raising resources exclusively for the Centre. Honourable Members are aware that a new provision was made last year for levying auxiliary duties of excise on all excisable goods at an amount equal to 20 per cent of the value of the goods. These levies were restricted to certain selected items at a level needed to meet the demands of the Centre then. I propose to continue this provision for another year. While the effective levies on the items chosen last year will remain unchanged, I propose to add selectively some more to the list.

52. Briefly, my proposal is to levy auxiliary duties at the rate of ten per cent of the effective basic duty on unmanufactured tobacco, cigarettes, smoking mixtures, plywood and cement; at the rate of twenty per cent of the effective basic duty on dye-stuffs, optical bleaching agents, gases, rubber products and plastics; at the rate of thirty-three and one-third per cent of the effective basic duty on paints and varnishes; and at the rate of fifty per cent of the effective basic duty on aerated waters, glycerine, cosmetics and toilet preparations. Through these proposals and as a result of the modifications of the basic excise duties I am proposing on the existing items, I expect to raise Rs. 62.38 crores in a year, by way of auxiliary duties.

53. In the case of steel as well as other metals, the auxiliary duties are proposed to be applied only to indigenous production and will not be attracted by way of counter-vailing duty on imports, as hitherto. I propose to extend a similar exemption in the case of plastics.

54. In the sphere of basic excise duties, my proposals naturally cover a wider range and have been made with the multiple objects of rationalisation, curbing consumption, mopping up fortuitous gains and, not the least important, I must confess, raising revenue. In November, 1973, following successive increases in crude oil prices and cuts in crude oil supplies, and as one of a series of measures, the basic excise duty on motor spirit was raised from Rs. 1,000 per kilolitre to Rs. 2,000 per kilolitre. In view of the continuing need for exercising restraint and economy in the consumption of a number of other petroleum products, and to prevent their misuse, I propose to increase substantially the basic excise duties in respect of "special boiling point" spirits, raw naphtha intended for methanol and petrochemicals, benzene etc. used for a variety of purposes, asphalt and bitumen, mineral turpentine oil, waxes and blended or compounded lubricating oils and greases. Through these proposals, I expect to raise an additional revenue of Rs. 22.48 crores from the petroleum group.

55. The rates of excise duty on various types of motor vehicles have remained unchanged for some years now. I, therefore, propose to rationalise the rates of duty by replacing the existing alternative rates by *ad valorem* rates. I intend imposing a uniform rate of 9 per cent *ad valorem* on vehicles like scooters, motor



cycles, mopeds, auto-rickshaws and other three-wheelers. Motor vehicles of not more than 16 H.P. by R.A.C. rating, which cover passenger-cars, jeeps, etc., are at present assessable at a rate of duty of 13.33 per cent *ad valorem*. I propose to increase this rate to 20 per cent *ad valorem* in respect of vehicles with body and to 25 per cent *ad valorem* in respect of others, including those cleared as drive-away chassis. Big-sized cars will pay a higher duty at 40 per cent *ad valorem*.

56. Commercial vehicles have had the benefit of concessional 'specific' rates fixed some years ago. I propose to discontinue these and impose a uniform *ad valorem* rate of 12½ per cent. In that process, certain extra-heavy vehicles, which are at present paying duty at the tariff rate, will get an incidental benefit of 2½ per cent. I do not, however, propose to change the existing rates on tractors and trailers.

57. The proposals relating to motor vehicles are estimated to net an additional revenue of Rs. 16.25 crores.

58. As part of the socio-economic objectives of the Government, I have some proposals to restrain consumption by the more affluent section of the community. The existing rates of duty on refrigerators, air-conditioners, refrigerating and air-conditioning machinery, appliances, and parts, are being stepped up, with certain modifications in respect of a few existing exemptions. The present concessional rates in favour of public-run hospitals, cold-storage plants and factory establishments are not, however, being disturbed. These changes are expected to bring in additional revenue of Rs. 5 crores in a year.

59. Some of the manufacturers of T.V. sets have been regaling us with advertisements exhorting the public to "budget for a T.V. set" to forestall the Central Government Budget. As a compliment to these soothsayers on the accuracy of their prediction, I propose to increase the duty on T.V. sets from 10 per cent *ad valorem* to 20 per cent *ad valorem*. Extended play records are also being brought within the dutiable category. While these proposals will make entertainment costlier for the wealthy, I am anxious that music, entertainment and knowledge should reach the less privileged in wider measure at lesser cost. To this end, I propose to exempt totally all radio-sets produced in the small-scale sector and sold to the consumer at a price of not more than Rs. 225 per set. These measures are estimated to bring in a net revenue of Rs. 1.20 crores.

60. I have been avoiding major changes in the rates of duties on various cotton textiles, including cotton yarn, except to the limited extent of raising resources for the States. The rates of duty are 'specific' and were fixed in 1969 at a time when the industry was beset with difficulties. There is, therefore, a clear need for revision, especially as the industry has since recovered. Cotton textiles being an item of mass consumption, I am quite alive to the need for forbearance in increasing the rates of duty on certain categories of yarn and fabrics. My proposals, therefore, cover only super-fine, fine and medium-A fabrics, which are subjected to sophisticated processes, such as, mercerising/shrink-proofing/sanforizing. In the case of cotton yarn, the escalations are confined to higher count groups. I have, however, not disturbed the existing exemptions and concessional rates in respect of yarn in straight-reeled hanks mostly consumed by the handloom sector. I have also rationalised certain exemptions and compounded levy rates. These measures relating to cotton yarn and cotton fabrics are estimated to yield an additional revenue of Rs. 22.05 crores.

61. As a measure of rationalisation, which will also earn revenue, I propose to increase the existing two rates of duty on polyester fibre to a uniform rate of Rs. 40 per kilogram. Suitable increases in the existing rates applicable to different denier groups of polyester filament yarn, sympathetic revisions in the rates of duty on staple fibre spun yarn, certain categories of blended yarn, and an increase in the rate of duty on resin-bonded slagwool, are also being proposed. These proposals would bring in an additional revenue yield of Rs. 13.99 crores.

62. In regard to iron or steel, I propose to rationalise certain exemptions relating to pig iron, steel ingots and products produced with the aid of electric furnace, and to products made out of duty-paid cut-pieces of steel ingots, which will result in an additional revenue of Rs. 7.20 crores.

63. The rates of duty for various categories of paper and board are 'specific' and require review from time to time. I propose to make suitable upward revisions in the existing rates on paper and paper board, apart from rationalising certain exemptions and classifications. The concessional rate of 15 paise per kilogram applicable to the

commoner varieties of printing and writing paper falling within the grammage limit not exceeding 65 grammes per square metre, the total exemption in favour of news-print, hand-made paper and board, as well as existing concessions for smaller paper mills and newly established units will, however, continue. These measures will result in an additional revenue of Rs. 10 crores.

64. As straight revenue-raising measures, I propose to increase by 5 per cent *ad valorem* the existing rates of duty on surface active agents, office machines, metal containers, rolling bearings, welding electrodes, coated abrasives and grinding wheels, dry batteries, certain categories of glass and glassware, chinaware and porcelainware and thereby raise an additional revenue of Rs. 20.17 crores.

65. As a part of our efforts to mobilise resources, I propose to levy for the first time excise duties at varying rates on tooth-paste (including dental cream), electrical stampings and laminations, specified cutting tools, tape and cassette recorders, cast-alloy permanent magnets and sensitised photographic paper and board. In the matter of new levies, Members will be reassured to know that suitable exemptions for smaller manufacturers have been provided wherever necessary. These new levies would bring in an additional revenue of Rs. 8.20 crores.

66. Some minor proposals for changes in excise duty will yield an additional Rs. 3.05 crores. The proposals relating to excise duties account for a net gain in revenue of Rs. 191.97 crores in 1974-75, of which Rs. 25.92 crores will accrue to the States and Rs. 166.05 crores to the Centre.

### CUSTOMS DUTIES

67. In the matter of customs duties, in view of the mounting world-wide shortages and unprecedented rise in international prices of a wide array of imported goods, my proposals in regard to import duties are no more than marginal. Briefly I propose to continue for another year the auxiliary duties of customs and the exemptions relating to them, with a slight modification. At present, these duties are levied at three differential rates of 20 per cent, 10 per cent and 5 per cent. I propose to raise the rate applicable to the middle slab from 10 per cent to 15 per cent. This modification will yield an additional revenue of Rs. 18 crores in a full year.

68. The only other proposal I have to make concerns whisky, brandy, gin and certain other spirits by way of an increase in the basic duty from Rs. 60 per litre to Rs. 80 per litre. While society at higher levels may, as a result, have to pay a little more for their spirituous relaxation, it will help me in getting some revenue for the exchequer.

69. Inclusive of additional duties, consequential to the changes in excise duties, the additional revenue from import duties will amount to Rs. 20.03 crores annually.

70. Taking Customs and Central Excise duties together and exclusive of States' share, the additional revenue accruing to the Centre will be of the order of Rs. 186.10 crores in a full year.

### POSTS AND TELEGRAPHS

71. I need now to say a word on behalf of my colleague the Minister of Communications. As the House is aware, postal rates have not kept pace with rising costs. The frequent increases in Dearness Allowance and the heavy additional expenditure incurred on account of implementation of the Pay Commission's recommendations have further pushed up the establishment cost in the Postal Branch which is highly labour oriented. On the Telecommunications side, also, the operational costs as well as the cost of equipment required for various projects have been going up steadily. The Department's developmental programme to improve the Trunk Telephone Service by provision of high grade media like Microwave and Co-axial systems, to install new Exchanges and expand existing ones for meeting the fast growing demand for telephone connections and to expand the Trunk Dialling and Teleprinter facilities all entail heavy investments. These various factors necessitate an upward revision of tariffs in the Postal, Telegraph and Telephone Branches of the Department. A Memorandum showing the proposed changes in the Posts and Telegraphs Tariffs is being circulated along with Budget papers. I shall therefore mention only the more important changes.

72. The tariff for Postcards is proposed to be increased from 10 Paise to 15 Paise. Even after this revision, the Department will be incurring a loss of Rs. 2.43 crores per annum in running this service. It is proposed to raise the rate of Lettercards from 15 Paise to 20 Paise and that of Letters weighing upto 15 grams from 20

Paise to 25 Paise. The Registration Fee is being increased from Re. 1/- to Rs. 1.25 and the Parcel rate from Re. 1/- for every 400 grams to Rs. 1.50 for every 500 grams. The Posting Fee for Value Payable Post and the tariff for Business Reply Permits are being revised. The minimum charge for a Non-Press Telegram of 'Ordinary' category with eight words or less is being increased from Rs. 1.20 to Rs. 1.50 and for the 'Express' category from Rs. 2.40 to Rs. 3.00. The charge for each additional word will, however, remain the same. It is also proposed to increase the rental for telephone connection both in the 'measured rate systems' and the 'flat rate systems'. As against this, the number of free calls allowed during a quarter will be raised from 250 to 300. The rate for each additional call after 300 will be increased from 20 Paise to 25 Paise. The Trunk Call rate structure is being rationalized. While this will involve increase in Trunk Call charges for distances between 100 and 1300 kilometres, in respect of calls between stations within 20 kilometers, only the unit fee of 25 Paise will be charged for an 'ordinary' call as against the present 50 Paise for such calls.

73. These tariff revisions are estimated to bring in additional revenue of Rs. 57.08 crores per annum. The changes would be given effect to from dates to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament. The yield during the financial year 1974-75 will be of the order of Rs. 42.80 crores.

74. The results of these changes have been accounted for in reckoning the internal resources of Posts and Telegraphs Department.

75. So far as the Union Budget is concerned, the various proposals would imply, for 1974-75 additional revenue aggregating Rs. 186 crores. The budgetary gap of Rs. 311 crores I had indicated earlier will accordingly be now scaled down to Rs. 125 crores.

76. In conclusion, I would like once again to draw the attention of the House to the developments of last two years which have shown how certain events can greatly upset the original budgetary calculations. In the year ahead lie more sources of uncertainty than ever before, which must be tackled speedily and with flexibility. I would, however, like to say that we do not propose to allow these uncertainties to blur our vision of the future. The social and economic problems that we currently face can be resolved in the long run only in the frame-work of a rapidly expanding economy with socialist objectives. I trust this budget is one more step in that direction.

